Corporations, Banks, Insurance Corporations and in such other Central/State Government Organisations; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): (a) and (b) Disparities exist between pay, allowances and perquisites of Central Government employees and employees of the Public Sector Undertakings, Banks and Insurance Corporations. While it is not possible to bring complete uniformity in this regard because of historical factors and differences in the conditions of service and employment, in order to ensure that unreasonable disparities do not occur, Public Sector Undertakings etc. are required to obtain prior concurrence of Government for general revision of pay and allowances of their employees.

As regards State Governments, the position is that under entry 41 of the State List in the seventh Schedule of the Constitution, State public services fall within the exclusive purview of the State Governments. The question of revision of scales of pay of the State Government employees is, therefore, entirely a matter for the State Governments to consider.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का खोला जाना

1511. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अब तक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) अग्रणी योजना के अधीन अब तक गांवों में कितनी राशि ऋण के रूप में बांटी गई है और कितनी राशि जमा की गई है; और

(ग) जमा की गई राशियों में से गांवों में कितनी राशि के ऋण बांटे गये हैं और अन्य स्रोतों से कितनी राशि के ऐसे ऋणों की व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पूजारी): (क) 19.7.69 (जिस तारीख को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 31.3.84 की स्थिति के मुताबिक देश में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जनसंख्या समूहवार वितरण के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	केन्द्रों में कार्यालयों की संख्या			
	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहर/महानगरीय पत्तन शहर	जोड़
31.3.1984	24770	9205	1068	44583
19.7.1969	1860	3344	3117	8321
वृद्धि	22910	5861	7801	36262

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमा संग्रह, संवितरित सकल बैंक ऋण और ऋण जमा अनुपात के सम्बन्ध में जून 1981, जून 1982 तथा जून 1983 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

करोड़ रुपए

जून, 1981		जून, 1982	जून, 1983
जमा रकमें	5253·97	6464·22	7656·70
ऋण	3031·94	3792·00	4587·78
ऋण: जमा अनुपात	57·7	58·7	59·9

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्र की गई जमा राशियों का वितरण केवल ऐसे क्षेत्रों में किया जाए, बैंकों से उनकी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के वास्ते अलग से 60 प्रतिशत की ऋण: जमा अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है ।

वित्त मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1512. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन तीनों विभागों के मुख्यालयों में कार्यरत राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और पिछले वर्ष आयोजित की गई चारों बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग न लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं और उन बैठकों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उन्होंने भाग नहीं लिया;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और उसके प्रचार के कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति का पता लगाने के लिए पिछले वर्ष समिति द्वारा जिन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, उनके नाम क्या हैं और सभी कार्यालयों का निरीक्षण पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे; और

(ग) क्या किसी विभाग ने अधीन कार्यरत सभी कार्यालयों का निरीक्षण पूरा कर लिया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) वित्त मंत्रालय के तीनों विभागों में से प्रत्येक में अलग-अलग राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने पदनामों से नियुक्त किए जाते हैं और वे अथवा उनके प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जो विभिन्न कारणों से समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले सके ।

(ख) और (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/69/69-रा. भा. में निर्धारित किए गए हैं और कार्यालयों के निरीक्षण का काम उनमें शामिल नहीं है ।

वाणिज्य मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

1513. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कितनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं और पिछले वर्ष के दौरान किस-किस तारीख को उनकी बैठक हुई;

(ख) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित कार्य के विकास और प्रचार की देख-रेख करने के लिए इन समितियों द्वारा, अलग-अलग, कितने विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है; और